हरिभूमि

महासमुंद भूमि

रायपुर, शुक्रवार 5 जून 2026

तापमान

अधिकतम 39.2 डिग्री

न्यूनतम 29.6 डिग्री

12 किसानों के समितियों से खाद लेने के साथ ही...

12 नपाध्यक्ष के निर्देश पर बड़ी नालियों की सफाई शुरू...

खबर संक्षेप

मारपीट करने वाले आरोपी के विरूद्ध जुर्म

महासमुंद। ग्राम हरदा में एक व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले में आरोपी के विरूद्ध जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस को प्रार्थी हरमेश सारथी पिता धरम लाल सारथी ने बताया कि 2 जून को रात करीबन 09.30 बजे आरोपी डोस कुमार सारथी पिता प्रेमलाल सारथी (40 साल) ने तेजकुमार यादव के घर के पास आकर, हमारी दीदी मां बुधनी बाई को खाना पीना नहीं देते हो कहकर गाली गलौज करते हुए डंडे से मारपीट की। रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 296, 115 (2), 351 (3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

महुआ शराब जब्त, महिला पर कार्रवाई

महासमुंद। बसना पुलिस ने एक महिला के कब्जे से महुआ शराब जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबीर सूचना पर पुष्पा सोनी पति घनश्याम सोनी (36 साल) वार्ड नं- 01 बसना के कब्जे से करीब 15 लीटर महुआ शराब कीमत 3000 रुपए को बरामद कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

रेलवे फाटक के पास एक्सीडेंट में कार क्षतिग्रस्त

महासमुंद। न्यायालयीन कार्य से महासमुंद आए अधिवक्ता की कार को एक वाहन चालक ने ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। कोतवाली थाने में प्रार्थी नितिन चतुर्वेदी निवासी रायपुर ने रिपोर्ट लिखाई है कि 3 जून को अपनी कार सीजी 04 पीबी 1508 से अपने साथी अधिवक्ता अमन जांगडे एवं एक परिचित श्याम सुंदर गुप्ता के साथ रायपुर से महासमुंद शहर की ओर न्यायालयीन कार्य से आ रहा था। शाम 05 बजे के आसपास महासमुंद रेलवे फाटक के पास कार सीजी 06 एचई 8881 के चालक ने उसकी गाड़ी को पीछे से ठोकर मार दिया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। मामले की रिपोर्ट पर आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध धारा 281, 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

अंग्रेजी शराब जब्त, एक व्यक्ति पर कार्रवाई

महासमुंद। ग्राम बेमचा की ओर जा रहे एक व्यक्ति के कब्जे से कोतवाली पुलिस ने अंग्रेजी शराब बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक प्लास्टिक बोरी में बड़ी मात्रा में अवैध शराब लेकर बेमचा शराब भट्ठी से पैदल ग्राम बेमचा की ओर जा रहा है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी गणेश यादव पिता गोकुल यादव (43 वर्ष) बेमचा के कब्जे से 8 नग देशी रोमियो पौवा शराब कीमत 800 रुपए, 22 नग मेडोफ प्रीमियम माल्ट व्हिस्की अंग्रेजी शराब कीमत 3520 रुपए कुल 4320 रुपए को बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ धारा धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

रात में पेड़ काटकर ठूंठ भी छिपा रहे, सरकारी जमीन हथियाने की तैयारी

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

■ पेड़ों की कटाई मामले में संबंधित विभाग मौन

जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम साराडीह के आसपास तथा गौठान क्षेत्र में हरे भरे पेड़ों की निर्बाध कटाई जारी है। पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण के लिए एक तरफ जहां सालाना करोड़ों का बजट खर्च हो रहा है वहीं हरे भरे पड़ों की हो रही कटाई पर संबंधित विभाग पूर्णतः मौन धारण किए हुए हैं। जबकि, ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमी लगातार इससे विभाग के कर्मियों और अफसरों को सूचित भी कर रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, साराडीह गौठान क्षेत्र में पेड़ों को काटने का काम मुख्य रूप से शाम के समय किया जाता है। अंधेरा होते ही पेड़ों को काटकर उनकी लकड़ियां हटा दी जाती हैं। पेड़ों को काटने के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए ठूंठ और जड़ों को मिट्टी से ढंक दिया जाता है। ताकि किसी को पता न चले कि यहां कभी पेड़ थे। इस तरह की व्यवस्थित तरीके से की जा रही अवैध कटाई से स्पष्ट है कि यह सोची-समझी योजना का हिस्सा है। और इस सरकारी जमीन को गुपचुप तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।

पर्यावरण संरक्षण के नाम पर बजट हो रहा खर्च, और अवैध कटाई पर चुप्पी

विभागीय लापरवाही और चुप्पी

सबसे गंभीर बात यह है कि वन विभाग और राजस्व विभाग दोनों ही इस मामले में पूरी तरह से बेखबर बने हुए हैं। गौठान क्षेत्र सरकारी भूमि के अंतर्गत आता है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की है। इन पर कोई कार्रवाई न होने से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी इस अवैध गतिविधि को देख रहे हैं। लेकिन, अनदेखा कर रहे हैं।

सरकारी बजट और धरातल की सच्चाई

एक तरफ सरकार पर्यावरण बचाने पौधरोपण अभियान चला रही है और इसके लिए लाखों-करोड़ों का बजट आवंटित है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की अंधाधुंध कटाई से सरकारी प्रयासों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि गौठान क्षेत्र में ही पेड़ों को इस तरह नष्ट किया जाता रहा, तो क्षेत्र का हरित आवरण पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जिले के जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि साराडीह मोड़ के पास गौठान क्षेत्र में चल रही पेड़ों की कटाई की तत्काल जांच की जाए।

प्रदर्शन : एसडीएम कार्यालय में सौंपा गया सीएम के नाम ज्ञापन

खाद-बीज, डीजल संकट, कांग्रेस ने रैली निकालकर किया विरोध

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

जिले के हजारों छोटे और सीमांत किसान इन दिनों खेती के लिए जरूरी संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। खाद-बीज की किल्लत, डीजल वितरण में प्रशासनिक पाबंदियों और अव्यावहारिक सरकारी नीतियों के विरोध में गुरुवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस की जिला इकाई ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस भवन से पैदल रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय की ओर रवाना हुए और मुख्यमंत्री के नाम अफसरों को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वर्तमान में किसान सुबह से ही सहकारी समितियों और बाजार में खाद और बीज की तलाश में निकलते हैं, लेकिन शाम तक उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। रसूखदार लोगों को तो आसानी से खाद-बीज मिल रहा है, जबकि आम और गरीब किसान पूरी तरह बेबस है। किसान कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि केवल भाषण और दिखावे से किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी, प्रशासन को अब धरातल पर काम करने की जरूरत है।

9 सूत्रीय मांग

किसान कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से इन प्रमुख समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है जिसमें प्रति एकड़ खाद की मात्रा कम करने का फरमान अव्यावहारिक है। इसे तत्काल वापस लेकर किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद दी जाए। वर्तमान में 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को तीन किश्तों में खाद देने का नियम है। किसान बार-बार समितियों के चक्कर नहीं काट सकते, इसलिए खाद एक बार में उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीण पेट्रोल पंपों पर ट्रैक्टर लेकर जाना अनिवार्य कर दिया गया है और मात्र 1000 रुपए का डीजल दिया जा रहा है। भीषण गर्मी में खेती का काम छोड़कर ट्रैक्टरों की कतार में लगना किसानों के लिए बड़ी मुसीबत है। मांग की गई है कि जेरकिन या कैन में डीजल देने की अनुमति दी जाए। धान की एकमुश्त राशि और लंबित कृषि अनुदान का भुगतान जल्द किया जाए।

यह रहे आंदोलन में मौजूद

रैली और ज्ञापन सौपे जाने के कार्यक्रम में किसान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर, वरिष्ठ कांग्रेसी सेवन लाल चंद्राकर, दाउलाल चंद्राकर, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश जैन, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानिक साहू, डॉ. रश्मि चंद्राकर, अंकित बागबाहरा, मोक्ष प्रधान, दीपक पांडेय, प्रतीक तिवारी, मोहित ध्रुव, खिलावन बघेल, अन्नू चंद्राकर, खिलावन साहू, ढेलू निषाद, बर्मिल जैन, सोनम बंसोड़ सहित जिले भर से पहुंचे किसान कांग्रेस और कांग्रेस पदाधिकारीगण मौजूद रहे।

पत्रकार वार्ता भी ली

रैली और ज्ञापन आंदोलन के पूर्व किसान कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि धान के मुख्य उत्पादक प्रदेश में किसान इन दिनों यूरिया और उर्वरक की किल्लत से परेशान है।

किसानों के लिए प्रति एकड़ सीमा तय करते हुए कई चरणों में भाजपाई सरकार सोसायटियों के चक्कर लगाने मजबूर कर रही है। देश में यूरिया का संकट नही है बल्कि भाजपा सरकार द्वारा किसानों को परेशान करने के लिए पैदा किया गया कृत्रिम संकट है।

किसान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 2 जून से शुरु हुए अभियान के तहत महासमुंद में विरोध प्रदर्शन किसान कांग्रेस का तीसरा कार्यक्रम है। मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए लाभप्रद योजना नरवा, गरवा, घुरुवा और बाड़ी को बंद किए जाने के चलते भी खाद का संकट से प्रदेश किसान जूझ रहे हैं।

खुलासा : लव ट्राएंगल, दोस्त की हत्या कर बोर से बांधा, आरोपी गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

गांव की एक बाड़ी के बोर पंप में बंधी लाश के मामले में दोस्त द्वारा ही लव ट्राएंगल के चलते अपने दोस्त की जान ले लेने की बात सामने आई है। जिले के बसना थाना क्षेत्र के भंवरपुर चौकी के ग्राम झारउड़ेला में हुए हत्याकांड को पुलिस ने चंद घंटों के भीतर सुलझा लिया।

पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एक जून को चौकी भंवरपुर को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोंगरे भोई पिता रविलाल भोई (30 साल) ग्राम झारउड़ेला मृत अवस्था में गांव के रविशंकर पटेल की बाड़ी में बोर के पास पड़ा हुआ है, जिसकी मृत्यु संदेहजनक है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पाया कि मृतक मोंगरे भोई के सिर में चोट लगने से खून निकला था, साथ ही चादर के टुकड़े से उसके गले को लपेटना पाया गया, इसके अलावा उसके शरीर पर संघर्ष के निशान मौजूद थे। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में चिकित्सक ने मृत्यु का कारण हत्यात्मक होना बताया। जिसके बाद अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 103(1) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया।

पुलिस न गवाहों से पूछताछ पर गांव के व्यक्ति वेदराम पटेल से मृतक का फोन पर अंतिम बातचीत होना तथा वेदराम पटेल द्वारा मृतक को बुलाने पर मृतक के वेद राम के घर जाने जाने की जानकारी मिली। पुलिस ने वेदराम की तलाश शुर की तो वह अपने आवास से फरार मिला। इसके बाद तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी वेदराम को पकड़ा गया और पूछताछ में आरोपी वेदराम ने त्रिकोणीय प्रेम संबंध के कारण मृतक मोंगरे भोई को रास्ते से हटाने की नीयत से जानलेवा हमला कर सिर एवं गर्दन में चोट पहुंचाकर हत्या करना अपराध स्वीकार किया। आरोपी मृतक का मोबाइल लोअर एवं चप्पल को अलग-अलग जगहों में छिपा दिया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

शिकार मामले में संलिप्त एक गिरफ्तार, तीन फरार

महासमुंद। बार परिक्षेत्र के बसना सर्कल के ग्राम पड़कीपाली व अकलतरा में टीम ने दबिश देकर शिकार के मामले में संलिप्त एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी बार संजय कुमार ठाकुर एवं सहायक परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी रणवीर सिंह मरावी के नेतृत्व में वन विकास निगम की टीम ने आरोपियों की पतासाजी के लिए लारीपुर बीट के ग्राम पड़कीपाली एवं अकलतारा पहुंची थी। टीम ने घेराबंदी कर मनोहर यादव (32) को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान तीन अन्य पड़कीपाली निवासी लोकेश भोई व सेवक राम भोई और ग्राम अकलतरा निवासी राजू मांझी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। सांकरा पुलिस ने आरोपी मनोहर को बुधवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया।

फरार आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी

परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी (बार) संजय कुमार ठाकुर ने बताया कि फरार तीनों आरोपियों की पहचान सुनिश्चित कर ली गई है और उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अज्ञात वाहन की टक्कर से एक की मौत

महासमुंद। ग्राम केंदूढार के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक चालक की मौत हो गई। मामले की रिपोर्ट सरायपाली थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बताया कि थाना सरायपाली के मर्ग क्रमांक 37/26 धारा 194 बीएनएसएस के मृतक चमार सिंग चौहान पिता ज्ञान सिंग (36 वर्ष) बिरसिंगपाली की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि मृतक चमार सिंग चौहान 3 जून को मोटर सायकल स्प्लेंडर प्लस सीजी 06 एचएफ 7562 से सरायपाली काम करने आ रहा था। सुबह करीब 8 बजे केंदूढार के पास पहुंचा था तभी पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे ठोकर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपी अज्ञात वाहन चालक के विरूद्ध धारा 106(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

गांव की मीटिंग में विवाद, दो पक्षों के बीच मारपीट

महासमुंद। ग्राम मुढ़ेना में मीटिंग के दौरान दो पक्षों के बीच मारपीट के मामले में आरोपियों के विरूद्ध अलग-अलग मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को टीकम विश्वकर्मा ने बताया कि 03 जून को ग्राम पंचायत मुढेना में मीटिंग हो रही थी, जिसमें गांव के करीबन 30-40 लोग शामिल थे। दोपहर करीबन 03 बजे गांव के विकास ठाकुर ने मीटिंग में गांवकारी सियान टीआर सिन्हा को बिना बताये मीटिंग रखे हो बोल रहा था। जब उसने उसे चिल्लाने से मना किया तब विकास ठाकुर, उसके साथी भूषण ठाकुर एवं राजेश साहू ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया है। दूसरी ओर उपसरपंच राजेश साहू ग्राम मुढ़ेना ने कोतवाली पुलिस को बताया कि 03 जून को गांवकारी बैठक हो रही थी। जिसमें गांव के विकास के संबंध में चर्चा कर रहे थे। दोपहर करीबन 3 बजे गांव के टीकमचंद विश्वकर्मा पिता मनहरण विश्वकर्मा द्वारा अनर्गल बातें कही जा रह थी, जिसका उप सरपंच होने के नाते उसने विरोध किया, जिस पर टीकमचंद विश्वकर्मा गाली गलौज करते हुए हाथापायी करने लगा। जब विकास ठाकुर एवं भूषण ठाकुर के द्वारा बीच बचाव किया गया तो उनके साथ भी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट किया गया। मामले की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

ग्राहकों को नहीं मिल रही मीडियम रेंज की शराब, आपूर्ति प्रभावित

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

जिले की शराब दुकानों में इन दिनों मध्यम श्रेणी (मीडियम रेंज) की शराब की भारी कमी देखी जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा प्लास्टिक की बोतलों में शराब बेचने का नया नियम लागू किए जाने के बाद से आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है, जिसका सीधा असर मदिरा प्रेमियों पर पड़ रहा है।

आबकारी विभाग के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से जिले की सभी देशी और विदेशी शराब दुकानों में शराब की बिक्री कांच की बोतलों के स्थान पर प्लास्टिक की बोतलों में किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का उद्देश्य पैकेजिंग में बदलाव लाना था, लेकिन यह नियम अब शराब प्रेमियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। अनुबंधित कंपनियों द्वारा समय पर और पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक की बोतलों वाली शराब की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

स्टॉक की कमी से खाली हैं रैक

दुकान संचालकों का कहना है कि कंपनियों से आपूर्ति बहुत कम हो रही है। फिलहाल दुकानों में या तो कांच की बची हुई पुरानी बोतलें हैं या फिर प्लास्टिक की बहुत सीमित खेप उपलब्ध है। इस अव्यवस्था के कारण दुकानों में शराब का स्टॉक मेंटेन नहीं हो पा रहा है। सबसे ज्यादा समस्या मध्यम श्रेणी की शराब को लेकर है। दुकान पर आने वाले ग्राहकों का कहना है कि दुकानों में या तो बहुत महंगी शराब उपलब्ध है या फिर बहुत कम रेंज की शराब मिल रही है। आमतौर पर पसंद की जाने वाली आरएस, आरसी जैसी मध्यम रेंज की शराब दुकानों में उपलब्ध नहीं है। लोग लंबी दूरी तय करके दुकानों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं।

उपभोक्ताओं की परेशानी

मदिरा प्रेमियों ने बताया कि उन्हें 1500 रुपए तक की महंगी शराब तो आसानी से मिल रही है, लेकिन मध्यम वर्ग की पसंद वाली शराब नदारद है। दुकान के कर्मचारियों का कहना है कि जब तक कंपनियों से प्लास्टिक की बोतलों में पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती, तब तक यह स्थिति बनी रह सकती है। जिले के शराब प्रेमी अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस आपूर्ति श्रृंखला को जल्द से जल्द सुधारा जाए ताकि उन्हें अपनी पसंद की शराब खरीदने में असुविधा न हो। फिलहाल जिले की अधिकतर विदेशी शराब दुकानों में स्टॉक खत्म होने के बोर्ड या स्थिति साफ देखी जा सकती है।

बारिश के आसार, वातावरण में चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव

गर्मी से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

शहर के निवासियों के लिए बुधवार का दिन राहत लेकर आया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और पूरे दिन धूप और छांव का सिलसिला चलता रहा। बादलों और ठंडी हवाओं के कारण तेज गर्मी से लोगों को राहत महसूस हुई है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को महासमुंद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। इसी तरह न्यूनतम तापमान भी 27 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले तीन दिनों से लगातार तापमान में कमी दर्ज की जा रही है, जिसके कारण के भीषण गर्मी और लू के स्थान पर अब नम हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले समय के लिए अनुमान जारी किया है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं (अंधड़) चल सकती हैं। महासमुंद और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की मामूली वृद्धि हो सकती है, लेकिन आगामी तीन दिनों तक मौसम में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है।

मौसम को प्रभावित करने वाले कारण

मौसम विभाग ने बताया है कि वर्तमान में वातावरण में चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव बना हुआ है। यह स्थिति समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तारित है। इसके अलावा, दक्षिण गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के आसपास के हिस्सों में भी समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनी हुई है। इन मौसमी प्रणालियों के कारण वातावरण में नमी बनी हुई है, जिससे भीषण गर्मी से बचाव हो रहा है और बारिश की अनुकूल स्थितियां बन रही हैं।

महासमुंद के निवासियों के लिए यह राहत भरी खबर है कि भीषण गर्मी का दौर फिलहाल थम गया है और मौसम में नरमी बनी हुई है। हालांकि, तेज हवाओं और गरज-चमक की चेतावनी को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

सीएम हेल्पलाइन 1076 : शिकायत, समाधान और जवाबदेही का नया सिस्टम

केंद्रीकृत तकनीकी सिस्टम, फोन, वॉट्सएप, वेबपोर्टल, मोबाइल एप और लिखित आवेदन, दर्ज होगी शिकायत

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

हरिभूमि फॉलोअप

छत्तीसगढ़ में नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निराकरण के लिए राज्य सरकार 9 जून से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसका शुभारंभ करेंगे।

यह केंद्रीकृत तकनीक आधारित व्यवस्था नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने, शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने तथा समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का मंच प्रदान करेगी, जिसकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय द्वारा की जाएगी। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के अंतर्गत संचालित इस सिस्टम का उद्देश्य नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने, शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा समय पर समाधान तय करने विश्वसनीय मंच प्रदान करना है। नई व्यवस्था में शिकायतों का निराकरण 7 दिन में करने का प्रयास रहेगा। मुख्यमंत्री और उनका सचिवालय इसकी नियमित मॉनीटरिंग करेंगे, ताकि जनता को समय रहते राहत मिल सके। इस हेल्पलाइन का दूसरा पहलू यह भी है कि इसके जरिए कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी ले सकता है। पात्र हितग्राही को योजना का लाभ दिलाने के लिए मदद भी की जाएगी।

केंद्रीकृत और तकनीक आधारित प्रणाली

जानकारी के मुताबिक, सीएम हेल्पलाइन एक केंद्रीकृत और तकनीक आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के तौर पर तैयार की गई है। इसके माध्यम से नागरिक फोन, वॉट्सऐप, वेबपोर्टल, मोबाइल ऐप और लिखित आवेदन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट नंबर प्रदान किया जाएगा, जिससे उसकी ट्रैकिंग संभव होगी।

चार स्तरीय सिस्टम से समाधान

शिकायतों के समाधान के लिए चार स्तरीय सिस्टम विकसित किया गया है। इसमें पहले ब्लॉक, जिला, संभागीय तथा अंत में सचिव या विभागाध्यक्ष स्तर पर शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा में समाधान नहीं होने की स्थिति में शिकायत स्वतः अगले स्तर पर प्रेषित हो जाएगी।

यूनिक नंबर से होगी ट्रैकिंग

सीएम हेल्पलाइन प्रणाली के पांच प्रमुख बिंदु हैं, इसमें यूनिक टोकन नंबर के माध्यम से शिकायत ट्रैकिंग, समय पर समाधान के लिए एसएलआर आधारित व्यवस्था, समाधान के बाद नागरिकों से संतुष्टि फीडबैक, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा एमआईएस डैशबोर्ड के माध्यम से सतत निगरानी शामिल हैं। सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे संचालित रहेगा। कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा तथा उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी

हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है। हेल्पलाइन पर दर्ज हर शिकायत के लिए एक तय समय सीमा निर्धारित की जाएगी, जिसके भीतर संबंधित विभाग को कार्रवाई करनी होगी। यदि किसी शिकायत का समाधान निर्धारित समय में नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी और आम नागरिकों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

खबर संक्षेप

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन केवल राजनैतिक नौटंकी : कांग्रेस

रायपुर। कांग्रेस ने भाजपा सरकार द्वारा शुरू किये गए मुख्यमंत्री हेल्प लाइन को केवल राजनैतिक नौटंकी बताया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा, भाजपा सरकार जब से बनी है, उसे जनता की समस्याओं के निराकरण से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री निवास में हर गुरुवार को जनता से मिलने का कार्यक्रम शुरू हुआ था, ढाई साल में आधा दर्जन गुरुवार को भी मुख्यमंत्री लोगों से नहीं मिले। भाजपा सरकार ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मंत्रियों के नियमित बैठने की घोषणा की, वह भी बंद हो गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी बहुत जल्दी उबाऊ कॉल सेंटर में तब्दील होगा फिर बंद हो जायेगा। उन्होंने कहा, राज्य में सभी विभागों के सरकारी काम कितने दिन में होगा, हर काम को करने के लिए समय अवधि निर्धारित कर सिटीजन चार्टर बनाया गया था और वह आज भी लागू है, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के दफ्तरों में लगाया गया सिटीजन चार्टर का बोर्ड तक हटा दिया गया। किसी दफ्तर में कोई काम नहीं होता।

कोसरिया यादव समाज कार्यकारणी की बैठक 7 को

रायपुर। कोसरिया यादव समाज की रायपुर ग्रामीण परिक्षेत्र कार्यकारणी बैठक रविवार 7 जून को सुबह 11 बजे कुहेरा पाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुहेरा में आयोजित किया गया है। बैठक में कोसरिया यादव समाज रायपुर ग्रामीण परिक्षेत्र के समस्त पदाधिकारी, पाली अध्यक्ष व ग्राम गोटिया एवं समस्त यादव समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है। बैठक का उद्देश्य समाज को संगठित करने एवं युवाओं को आगे बढाने के विषय पर चर्चा की जाएगी।

लोकभवन में 3 दिवसीय मेडिटेशन शिविर

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका की पहल पर लोकभवन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तीन दिवसीय मेडिटेशन (ध्यान) शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता, कार्यक्षमता तथा तनाव प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना है। हार्टफुलनेस संस्था, अमलेश्वर के सहयोग से आयोजित इस शिविर के प्रथम दिन ध्यान के महत्व और उसके व्यावहारिक लाभों पर विस्तार से जानकारी दी गई।

उर्वरक वितरण में बड़ा बदलाव हो रहा है लागू

केंद्र के ई-पोर्टल से मिलेगी खाद, छत्तीसगढ़ के बीजापुर और गरियाबंद बने पायलट जिले

अब ऑनलाइन पंजीयन और डिजिटल निगरानी पर जोर

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

खास खबर

केंद्र सरकार ने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के वितरण को अधिक पारदर्शी और जरूरत आधारित बनाने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने की शुरुआत की है। इस नई प्रणाली के पायलट प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ के दो जिलों बीजापुर और गरियाबंद जिले का चयन किया गया है। खरीफ सीजन के दौरान इन जिलों में किसानों को उर्वरक वितरण ई-पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिससे खाद की उपलब्धता, वितरण और खपत की निगरानी रियल टाइम में की जा सकेगी। राज्य के कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था कारगर रही तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

नई व्यवस्था ऐसे समय लागू की जा रही है जब हर वर्ष खरीफ सीजन में खाद की कमी, लंबी कतारों, कालाबाजारी और जरूरत से अधिक खरीदारी की शिकायतें सामने आती रही हैं। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्रणाली से इन समस्याओं पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। हालांकि जून के प्रथम सप्ताह में राज्य में खेती-किसानी की गतिविधियां शुरु हो गई है। राज्य के कई अलग-अलग जिलों से किसानों की ये परेशानी सामने आ रही है कि उन्हें सोसाइटी से खाद नहीं मिल पर रही है। दूसरी ओर कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सोसाइटियों में खाद भंडारण पिछले साल से अधिक मात्रा में किया गया है। कुछ सोसाइटियों में खाद की कमी इसलिए हो सकती है, क्योंकि खाद परिवहन को लेकर कई बार समस्याएं आती हैं।

क्या है नई व्यवस्था

नई प्रणाली के तहत किसानों को उर्वरक प्राप्त करने के लिए पहले पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। किसान अपनी फसल, भूमि और आवश्यक उर्वरक की जानकारी दर्ज करेंगे। इसके आधार पर उन्हें उर्वरक आवंटित किया जाएगा। कई राज्यों में परीक्षण के दौरान ई-टोकन, क्यूआर कोड और भूमि रिकॉर्ड आधारित सत्यापन जैसी व्यवस्थाएं भी अपनाई गई हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला उर्वरक वास्तविक किसानों तक पहुंचे और उसकी अनावश्यक जमाखोरी न हो।

किसानों की चिंता भी कम नहीं

हालांकि नई व्यवस्था को लेकर किसानों और सहकारी समितियों के बीच कुछ आशंकाएं भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता और समय पर पंजीयन जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। मध्य प्रदेश में लागू की गई इसी तरह की डिजिटल प्रणाली से कतारें कम होने और वितरण में पारदर्शिता बढ़ने के दावे किए गए हैं, लेकिन शुरुआती दौर में किसानों को नई प्रक्रिया समझने में समय लगा था।

बीजापुर और गरियाबंद क्यों महत्वपूर्ण

बीजापुर और गरियाबंद का चयन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दोनों जिलों की कृषि परिस्थितियां एक-दूसरे से काफी अलग हैं। बीजापुर नक्सल प्रभावित और आदिवासी बहुल जिला है, जबकि गरियाबंद में धान उत्पादन प्रमुख है। ऐसे में केंद्र सरकार को यह समझने का अवसर मिलेगा कि डिजिटल उर्वरक वितरण प्रणाली दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों और सामान्य कृषि क्षेत्रों में किस तरह काम करती है। जानकारों का मानना है कि यदि इन दोनों जिलों में प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में इसे पूरे छत्तीसगढ़ और देश के अन्य राज्यों में लागू किया जा सकता है।

खाद संकट और कालाबाजारी रोकने की कोशिश

केंद्र सरकार का दावा है कि नई प्रणाली से उर्वरक की उपलब्धता और स्टॉक की निगरानी आसान होगी। अधिकारी यह देख सकेंगे कि किस जिले, ब्लॉक या दुकान में कितना स्टॉक उपलब्ध है और किस किसान ने कितना उर्वरक खरीदा है। इससे कालाबाजारी, फर्जी बिक्री और औद्योगिक उपयोग के लिए उर्वरक की अवैध निकासी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

खरीफ सीजन में होगी असली परीक्षा

छत्तीसगढ़ में धान की बुआई का मौसम शुरू होने वाला है और इसी दौरान उर्वरकों की मांग सबसे अधिक रहती है। ऐसे में बीजापुर और गरियाबंद में शुरू की जा रही ई-पोर्टल आधारित व्यवस्था की सफलता या विफलता पर राज्य और केंद्र दोनों की नजर रहेगी। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो खाद वितरण की पारंपरिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर, केंद्र सरकार उर्वरक वितरण को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर जरूरत के अनुसार खाद, सही किसान तक खाद की व्यवस्था विकसित करना चाहती है।

विभागों और कार्यों का किया गया स्पष्ट आवंटन

सीएम सचिवालय में अफसरों को सौंपे नए कार्यभार

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यों में व्यापक फेरबदल करते हुए नवीन उत्तरदायित्व सौंपे हैं। इस प्रशासनिक व्यवस्था के तहत प्रमुख सचिव से लेकर संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को उनके विभागों और कार्यों का स्पष्ट आवंटन किया गया है।

खास खबर

सुबोध कुमार सिंह, प्रमुख सचिव

इन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय के समस्त प्रशासनिक और समन्वय कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इनके पास राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, निर्वाचन आयोग, लोकपाल, केंद्रीय मंत्रालय, अन्य राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री कार्यालयों, नीति आयोग और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित विषय होंगे। इसके अलावा, ये विभिन्न आयोगों से संबंधित कार्य, मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रथम श्रेणी अधिकारियों का प्रबंधन, मुख्यमंत्री विशेष परियोजनाएं सीएम हेल्पलाइन, तथा कलेक्टर/एस.पी./ डीएफओ कांफ्रेस। साथ ही, ये सामान्य प्रशासन, वित्त, विधि एवं विधायी कार्य, खनिज साधन, तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रभारी रहेंगे।

मुकेश कुमार बंसल, सचिव

इन्हें जनसंपर्क, ऊर्जा, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन, मछली पालन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, जल संसाधन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का कार्यभार सौंपा गया है।

पी. दयानंद, सचिव

ये मुख्यमंत्री सहायता कोष (विवेकाधीन निधि) एवं स्वास्थ्य सहायता योजना, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.), वाणिज्यिक कर (पंजीयन) तथा संसदीय कार्य विभाग के कार्यों का संचालन करेंगे।

राहुल भगत, सचिव

इन्हें गृह, जेल, परिवहन, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग का उत्तरदायित्व दिया गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री निवास के समन्वय और बिल भुगतान संबंधी कार्य भी इनके अधीन होंगे।

रजत बंसल, विशेष सचिव

ये सुशासन तिहार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आवास एवं पर्यावरण, स्कूल शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग का कार्य देखेंगे।

प्रभात मलिक, संयुक्त सचिव

इन्हें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, श्रम, नगरीय प्रशासन एवं विकास, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, तथा जन शिकायत निवारण विभाग का कार्य आवंटित किया गया है।

संभाग एवं जिला स्तरीय निगरानी व्यवस्था

शासन ने संभागों के प्रभावी संचालन के लिए अधिकारियों को विशेष प्रभार दिए हैं, जिसके तहत वे संभाग/जिले की प्रमुख योजनाओं और महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करेंगे।

रायपुर संभागः मुकेश कुमार बंसल
बिलासपुर संभागः पी. दयानंद,
बस्तर संभागः राहुल भगत
सरगुजाः संभाग रजत बंसल
दुर्ग संभागः प्रभात मलिक।

आदेशानुसार, मुख्यमंत्री सचिवालय के सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ अपने कर्तव्यों का संपादन करेंगे और मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।

प्रदेश के पर्यटन स्थलों, हस्तशिल्प एवं स्थानीय उत्पादों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक देश के सबसे बड़े ट्रेड फेयर भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय मंच मिलेगा। इसी संबंध में कैट के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल से मुलाकात कर महोत्सव की रूपरेखा, पर्यटन आधारित व्यापारिक संभावनाओं और प्रदेश की सहभागिता को लेकर विस्तृत चर्चा की। कैट के राष्ट्रीय वाईस चेयरमैन अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमैन विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष परमानंद जैन ने संयुक्त रूप से बताया कि

भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के संबंध में गुरूवार को कैट अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल से मुलाकात कर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले भारतीय व्यापार महोत्सव के संबंध में विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन, वन एवं इको-टूरिज्म, होटल एवं ट्रैवल उद्योग, हस्तशिल्प, जनजातीय उत्पादों तथा स्थानीय उद्यमों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के विषय पर चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पर्यटन क्षमता को देशभर के व्यापारियों, निवेशकों एवं उपभोक्ताओं के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने महोत्सव में राज्य के पर्यटन विभाग, होटल उद्योग, ट्रैवल ऑपरेटर्स, हस्तशिल्प उत्पादकों, महिला स्व-सहायता समूहों एवं स्थानीय उद्यमियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के पर्यटन एवं व्यापार क्षेत्र को नई गति मिलेगी तथा रोजगार एवं निवेश के नए अवसर सृजित होंगे।

रेत खनन नियमों एवं वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप हो : राज्यपाल

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा है कि राज्य में रेत खनन निर्धारित नियमों एवं वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों उद्देश्यों को समान रूप से साधा जा सके। राज्यपाल ने राज्य में चल रही ड्रोन आधारित निगरानी और खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग की जानकारी लेते हुए इसकी सराहना की। राज्यपाल ने खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद से लोकभवन में चर्चा के दौरान यह बात कही। राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ की नदियों और बड़े नालों में रेत खनन की गतिविधियों को वैज्ञानिक, संतुलित और व्यवस्थित ढंग से संचालित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि रेत राज्य के विकास और आधारभूत संरचना निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए इसके उपयोग और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि इनके अनियंत्रित दोहन से पर्यावरण और जल संसाधनों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना बनी रहती है।

अवैध खनन पर हो प्रभावी नियंत्रण

राज्यपाल ने कहा कि नदियों और बड़े नालों की प्राकृतिक संरचना तथा जलधारण क्षमता को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अनियोजित खनन गतिविधियों से नदी तटों, भू-जल स्तर और स्थानीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए खनन कार्यों की नियमित निगरानी और अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि नदियों एवं जलस्रोतों की क्षमता बढ़ाने तथा भू-जल संरक्षण के लिए दीर्घकालिक और समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

रेत खनन क्षेत्र का हो वैज्ञानिक अध्ययन

राज्यपाल ने निर्देश दिए कि रेत खनन से संबंधित क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जैसे विशेषज्ञ संस्थानों से सर्वे और तकनीकी अध्ययन कराया जा सकता है, ताकि खनन गतिविधियों के प्रभावों का आकलन कर बेहतर प्रबंधन की दिशा में कदम उठाए जा सकें। राज्यपाल डेका ने कहा कि रेत जैसे खनिज संसाधनों का उपयोग राज्य के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मंत्री केदार ने कहा- किसानों को सुलभता से उर्वरक वितरण किया जाए

सहकारी समितियों के गोदाम में पर्याप्त रासायनिक खाद

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ सीजन की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश की सहकारी समितियों में सभी तरह की खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के किसानों को सुलभता से उर्वरक वितरण सुनिश्चित किया जावे।

खरीफ सीजन के लिए राज्य शासन द्वारा सहकारिता क्षेत्र के लिए रासायनिक उर्वरक का लक्ष्य 10 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध 3 जून तक की स्थिति में कुल लक्ष्य का 55 प्रतिशत उर्वरक का भंडारण किया जा चुका है। किसानों को 1.80 लाख मीट्रिक टन वितरण किया जा चुका है। राज्य में सहकारी समितियों के गोदाम में पर्याप्त रासायनिक खाद का स्टाक उपलब्ध है।

किसान खाद का अग्रिम उठाव कर लें

बरसात की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी गई है कि निर्धारित मात्रा के अनुरूप समितियों से खाद का अग्रिम उठाव कर लें। किसानों द्वारा संतुलित उर्वरक का उपयोग किया जाए। रासायनिक उर्वरकों के साथ अन्य उपाय जैसे हरी खाद, जैव उर्वरक,नीलहरित काई आदि के उपयोग हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

इतनी मात्रा में खाद

प्रदेश में वर्तमान स्थिति में यूरिया 251499 टन, डीएपी 69261 टन, इफको 119882 टन, पोटाश 38992 टन एवं सुपरफास्फेट 76297 टन का भंडारण किया गया, जिसमें से यूरिया 82623 टन, डीएपी 24957 टन, इफको 35809 टन, पोटाष 13762 टन एवं सुपरफास्फेट 23735 टन का वितरण किसानों को किया जा चूका है। समितियों के गोदाम में यूरिया 168876 टन, डीएपी 44304 टन, इफको 84073 टन, पोटाश 25230 टन एवं सुपरफास्फेट 52562 टन स्टाक उपलब्ध है।

सभी जिलों में लगेंगे केसीसी कैंप

कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देश अनुसार प्रदेश के सीमांत कृषकों को यूरिया एवं डीएपी एक बार में ही एक मुश्त प्रदान किया जावे। प्रदेश के लघु किसानों को निर्धारित मात्रा में यूरिया 2 किश्त में प्रदान किया जावें। बड़े कृषक जिनकी भूमिधारिता 5 एकड़ से अधिक है, को निर्धारित मात्रा में से यूरिया 3 किश्त में प्रदाय किया जाए। इसके अतिरिक्त सहकारिता मंत्री ने सभी जिलों में केसीसी के विस्तार हेतु कैप लगाने व सुशासन तिहार में अधिक से अधिक कृषकों को पैक्स समितियों के सदस्यता बनाने के निर्देश दिये।

अभनपुर के रिसार्ट में होगा आयोजन, राहुल खड़गे आएंगे

कांग्रेस जिला अध्यक्षों का विशेष प्रशिक्षण शिविर 21 से 30 तक

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

छत्तीसगढ़ के चम्पारण में 21 से 30 जून के बीच कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण अभनपुर के एक रिसार्ट में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मार्गदर्शन देने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी आएंगे।

ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य जिला अध्यक्षों को वैचारिक रूप से मजबूत करना और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना है। बताया जाता है कि दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा के जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ पीसीसी द्वारा 41 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पांच माह पूर्व की गई थी। नियुक्ति के बाद से उनकी पूरी

गतिविधियों की हर तीन माह में समीक्षा पीसीसी को करने कहा गया है। जिला अध्यक्षों को ज्यादा अधिकार देने की वकालत राहुल गांधी ने की थी। इसी आधार पर उन्हें प्रशिक्षण देकर संगठन के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में बताया जाएगा।

संगठन के वरिष्ठ नेता देंगे प्रशिक्षण

ट्रेनिंग कार्यक्रम में केंद्रीय संगठन के कई वरिष्ठ नेताओं के अलावा स्थानीय वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन देंगे। कार्यक्रम का शेड्यूल आने वाले दिनों में जारी किया जाएगा। बताया गया है कि कांग्रेस संगठन के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव केसी वेणुगोपाल इस दौरान आएंगे। वे संगठन में काम करने के बारे में बताएंगे। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिनों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी संबोधित करेंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिला अध्यक्षों को उनके अधिकार और संगठन के बारीकियों के बारे में बताएंगे।

संगठन को मजबूती के ट्रिक बताएंगे

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा सहित कई नेता भी इस शिविर में जिला अध्यक्षों को संगठन को मजबूती देने के बारे में बताएंगे। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के चयन के लिए ब्लॉक और बूथ स्तर तक नामों के संबंध में पूरी रिपोर्ट लेने के बाद नए जिला अध्यक्षों का चयन किया है। ऐसे में उन्हें अपने जिलों में संगठन को मजबूती और समन्वय से काम करने के संबंध में जानकारी देंगे।

खबर संक्षेप

विश्व पर्यावरण दिवस आज

महासमुंद। ग्राम खरोरा के संवेदना समूह खरोरा के सदस्य मुकेश चंद्राकर ने कहा कि धरती पर जीवन को बनाए रखने में एक पेड़ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। पेड़ों के बिना मानव जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। पेड़ों से न सिर्फ ऑक्सीजन मिलती है, बल्कि दैनिक उपयोग की हजारों वस्तुएं भी मिलती है। पेड़ का उपयोग जरूरत करें लेकिन किसी का आशियाना उजाड़कर नहीं।

दोपहिया चोर गिरफ्तार

रायपुर। आमानाका, क्राइम ब्रांच की टीम ने दोपहिया चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गाड़ी जब्त की है। दोपहिया चोरी करने के आरोप में पुलिस ने सरोना, बीएसयूपी कालोनी निवासी लक्की देवार को गिरफ्तार किया है। लक्की के खिलाफ नवीन चंद्रवंशी ने 26 मई को शराब दुकान के सामने से एक्टिवा चोरी कर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी।

हिस्ट्रीशीटर गांजा के साथ गिरफ्तार

रायपुर। तेलीबांधा थाने की पुलिस तथा एसीसीयू की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बुधवार को एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश के कब्जे से दो किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने अज्जू सिंधी उर्फ अजय मोटवानी के कब्जे से गांजा जब्त किया है।

एक साल से दर-दर भटक रहा वास्तविक हितग्राही, आवास योजना की राशि नहीं मिली, आवास मित्र की भूमिका पर भी उठे सवाल

हरिभूमि न्यूज ▶▶| सरायपाली

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि को लेकर जनपद पंचायत सरायपाली क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। एक गरीब हितग्राही पिछले लगभग एक वर्ष से अपनी ही स्वीकृत राशि प्राप्त करने के लिए कार्यालयों और जिम्मेदार लोगों के चक्कर काटने को मजबूर है। मामले में आवास मित्र की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम ग्राम पंचायत खैरझिटकी के सिंगारपुर निवासी हराधन भोई के नाम पर वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था। आरोप है कि योजना की राशि हितग्राही के खाते में जमा होने के बजाय उसके बड़े भाई नुराधन की पत्नी चित्रलेखा भोई के खाते में पहुंच गई। पीड़ित हितग्राही का आरोप है कि वह पिछले एक वर्ष से अपनी आवास राशि वापस पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कई बार संबंधित लोगों से निवेदन किया गया, पंचायत स्तर पर भी चर्चा हुई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकल सका। आर्थिक रूप से कमजोर हितग्राही अब तक अपना आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पाया है, जिससे उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आवास मित्र की भूमिका पर उठ रहे सवाल

मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि वास्तविक हितग्राही के लिए स्वीकृत हुई थी, तब वह राशि दूसरे व्यक्ति के खाते में कैसे पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि योजना से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी और दस्तावेजी कार्यवाही में आवास मित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में पूरे मामले में आवास मित्र की भूमिका भी संदेह के घेरे में दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि सभी नियमों का सही तरीके से पालन किया गया होता तो आज वास्तविक हितग्राही को अपनी राशि के लिए भटकना नहीं पड़ता। इसलिए मामले की जांच में आवास मित्र की भूमिका की भी गहन जांच किए जाने की मांग की जा रही है।

जनपद सीईओ को सौंपा आवेदन

न्याय नहीं मिलने से परेशान हितग्राही ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ), जनपद पंचायत सरायपाली को लिखित आवेदन सौंपकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि उसकी स्वीकृत राशि उसे दिलाई जाए तथा मामले में जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

गरीब परिवार का सपना अधूरा

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, लेकिन इस मामले में एक गरीब हितग्राही का अपने घर का सपना अधूरा पड़ा हुआ है। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे न तो राशि मिल पाई है और न ही आवास निर्माण कार्य शुरू हो सका है। अब पूरे मामले में प्रशासनिक जांच और कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह न केवल योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करेगा, बल्कि जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय करनी होगी।

किसानों को नहीं मिल रही खाद, बढ़ती कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाए सरकार : संजय चौधरी

हरिभूमि न्यूज ▶▶| सरायपाली

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष संजय चौधरी ने प्रदेश में किसानों को खाद की कमी एवं बढ़ती कालाबाजारी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

संजय चौधरी ने कहा कि खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में किसान डीएपी, यूरिया एवं अन्य आवश्यक उर्वरकों की कमी से जूझ रहे हैं। सहकारी समितियों और खाद वितरण केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानों पर खाद की कालाबाजारी एवं निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

उन्होंने कहा कि किसानों की परेशानी इस बात से और बढ़ गई है कि कई समितियों में प्रति एकड़ मात्र एक बोरी खाद ही उपलब्ध कराई जा रही है, जो खेती की वास्तविक आवश्यकता की तुलना में पूरी तरह अपर्याप्त है। खरीफ फसलों की समय पर बुवाई एवं बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है, लेकिन सीमित वितरण के कारण

किसानों को निजी दुकानों से अधिक कीमत पर खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे खेती की लागत बढ़ रही है और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

संजय ने कहा कि किसान देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन आज वही किसान अपनी फसल की तैयारी के लिए आवश्यक खाद प्राप्त करने में परेशान हैं। यदि समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हुई तो इसका सीधा असर खरीफ फसलों की बुवाई एवं उत्पादन पर पड़ेगा, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने राज्य सरकार एवं कृषि विभाग से मांग की कि सभी सहकारी समितियों और खाद विक्रेताओं के यहां पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा किसानों को उनकी वास्तविक आवश्यकता एवं भूमि रकबे के अनुसार खाद वितरित किया जाए। साथ ही कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों एवं बिचौलियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए नियमित जांच अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को निर्धारित दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि खाद संकट एवं कालाबाजारी पर शीघ्र नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों के हित में व्यापक जनांदोलन किया जाएगा।

दिव्यांगजनों का जीवन होगा सरल, सुगम और आत्मनिर्भर

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

- समाधान शिविर में मिला मोबाइल, एमआर किट एवं श्रवण यंत्र

सुशासन तिहार के अंतर्गत जिले में लगाए जा रहे समाधान शिविर जनसमस्याओं के निराकरण के साथ ही जरूरतमंद एवं पात्र हितग्राहियों को विभिन्न आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके जीवन सरल और सुगम बना रहे हैं। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचने से अनेक परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लौट रही है।

इसी कड़ी में महासमुंद शहरी क्षेत्र लोहिया चौक में आयोजित समाधान शिविर तीन दिव्यांग बच्चों के लिए नई उम्मीद और आत्मविश्वास लेकर आया। शिविर में दृष्टिबाधित दिव्यांग योगेश चंद्राकर को अध्ययन एवं संचार में सहायता के लिए टॉकिंग मोबाइल एवं स्पीकर प्रदान किया गया। इस उपकरण की मदद से वे अपनी पढ़ाई अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे तथा शैक्षणिक गतिविधियों में बेहतर सहभागिता सुनिश्चित कर पाएंगे। इसी तरह दिव्यांग हार्दिक को एमआर (मेंटल रिटार्डेशन) किट प्रदान की गई। यह किट उनकी स्मरण शक्ति, तार्किक क्षमता, एकाग्रता तथा आंखों और हाथों के समन्वय को विकसित करने में सहायक होगी। साथ ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास को गति मिलेगी। वहीं श्रवण बाधित दिव्यांग कान्हा मानिकपुरी को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। इस उपकरण के माध्यम से वे दैनिक जीवन की गतिविधियों, संवाद एवं सामाजिक सहभागिता में अधिक सहजता से जुड़ सकेंगे। समाधान शिविर में उनके परिजनों ने शासन की इस संवेदनशील पहल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर मिली सहायता उनके जीवन को अधिक सरल, सुगम और आत्मनिर्भर बनाने में विशेष योगदान देगा।

अमलोर में विभिन्न विकास कार्यों का विधायक योगेश्वर सिन्हा ने किया लोकार्पण

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

क्षेत्रीय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने गुरुवार को ग्राम अमलोर में 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें सीसी रोड, स्कूल में बाउंड्रीवाल शामिल हैं। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक सिन्हा के साथ आए हुए अतिथियों सहित ग्रामीणों ने विधि विधान से लोकार्पण किया। वहीं लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने ग्रामीणों से भेंट मुलाकात की। साथ ही नवविवाहित बहनों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा पूरा प्रयास है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए पूरे समर्पित भाव से विकास कार्यों का लाभ आप सभी को देता रहूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास की गति तेजी से चल रही है। वहीं हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में और आप सभी के आशीर्वाद से विकास कार्यों की धारा बह रही है। ग्रामीण

एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में रोड निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर, किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार अनेक विकास कार्य कर रही है। केंद्र एवं राज्य में डबल इंजन की सरकार अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है, जिसका लाभ आमजन तक पहुंच रहा है। राज्य में सुशासन के संकल्प को पूरा करने के लक्ष्य के साथ काम शुरू किया गया है।

यह रहे उपस्थित

मंडल अध्यक्ष डिगेश्वरी चंद्राकर, महामंत्री सुनील पटेल, भाजपा नेतागण रमेश साहू, प्रकाश पटेल, हनीश बग्गा, डॉ सोहन यादव, सरपंच रूपा जयप्रकाश, पंचगण भारत लाल निषाद, रामेश्वरी, दुर्गा निषाद, उषा निषाद, शत्रुहन निषाद सहित विकास चंद्राकर, अजय मंगल, गंगा प्रसाद ध्रुव, नंद किशोर यादव, मनोज यादव, चैत राम ध्रुव, डेविड चंद्राकर, टीकाराम पटेल, रामशरण दीवान, भानु पटेल, आकाश पांडे, अमित साहू, नईम खान, गंगाप्रसाद, राधेलाल, अश्वनी साहू, सियाराम, रामचरण व ग्रामीणजन उपस्थित थे।

शिक्षक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ प्रांतीय इकाई द्वारा प्रमुख संगठन मंत्री ओंकार सिंह ठाकुर, प्रांताध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष उमेश भारती गोस्वामी एवं महामंत्री मनोज राय के नेतृत्व में शिक्षा जगत से विभिन्न मांगों को लेकर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को ज्ञापन सौंपकर त्वरित निराकरण की मांग की गई।

संगठन के उप प्रांताध्यक्ष टेकराम सेन ने बताया कि प्रमुख मांगों में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भरती तथा पदोन्नति नियम 2026 के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में समस्त शैक्षिक संवर्गों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन शीघ्र किया जाए। विभाग में कार्यरत

शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) विभागीय स्तर पर आयोजित की जाए। रायपुर संभाग के पूर्व माध्यमिक प्रधान पाठकों को ई संवर्ग की पदोन्नति लंबे समय से लंबित है, शीघ्र पदोन्नति दी जाए। समस्त संवर्ग, साहयक शिक्षक से प्राचार्य तक के लंबित समयमान वेतनमान का शीघ्र निराकरण किया जाए। इसी प्रकार परीक्षा परिणामों की आड़ में अधिकारों से परे जाकर दंडित/प्रताड़ित करने जैसे कृत्यों पर रोक लगाई जाए। जांच न मांग के प्रकरणों का सेवानिवृत्त के तीन माह पूर्व निस्तारण किया जाए। उप प्रांताध्यक्ष टेकराम सेन ने बताया कि वर्षों के प्रतिक्षा के बाद प्राचार्य पदोन्नति का राह देखते देखते सैकड़ों शिक्षक सेवानिवृत्त हो गये उन्हें विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-108/2024/20-4, अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 30.04.2025 के अनुसार पत्र वरिष्ठता प्रदान की जाए। शिक्षक एलबी ग्रंथपाल शिक्षक एलबी संवर्ग में समायोजन की जाए। राज्य अतिथि शिक्षक के मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए छग शासन द्वारा जारी संविदा कर्मचारियों के नियम/शर्तों की भांति ही इन्हें भी सुविधा प्रदान की जाए। इन प्रमुख मांगों को लेकर प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा शिक्षा सचिव एवं डीपीआई से भेंट करते हुए शीघ्र निराकरण की मांग की गई है। उक्त जानकारी उप प्रांताध्यक्ष टेकराम सेन ने दी है।

अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत

रायपुर। आरंग थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बलौदाबाजार, गिरौधपुरी निवासी युवराज साहू (22), खिलेश्वर साहू (35) की मौत हुई है। घटना समोदा, करमंदी मार्ग के पास की है। दोनों युवक बाइक से जा रहे थे, इस दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को ठोकर मार दी। बाइक से गिरने पर युवराज तथा खिलेश्वर अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

आपसी रंजिश पर युवक के साथ मारपीट

रायपुर। खमतराई में एक युवक ने एक अन्य युवक तथा उसके साथियों के खिलाफ मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उरकुरा निवासी वासुदेव साहू ने अमन तथा उसके एक अन्य साथी के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है। वासुदेव ने पुलिस को बताया है कि अमन तथा उसके साथी ने आपसी रंजिश पर रास्ता रोक कर उसके साथ मारपीट की है।

सूने मकान में 11 हजार की चोरी

रायपुर। टिकरापारा थाना में एक व्यक्ति ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपने सूने मकान से छह हजार रुपए नकदी सहित 11 हजार रुपए का घरेलू सामान चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

जोगनीपाली पंचायत उपचुनाव में सुष्मिता जयप्रकाश को मिली बड़ी जीत

हरिभूमि न्यूज ▶▶| सरायपाली

उपचुनाव में सरपंच पद के लिए ग्राम पंचायत जोगनीपाली में सुष्मिता साहू ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को बड़े अंतर से पराजित कर सरपंच पद पर कब्जा जमाया। सरपंच पद रिक्त होने के कारण उपचुनाव कराया गया। इस चुनाव में कुल चार प्रत्याशी मैदान में थे। मतदान प्रक्रिया पीठासीन अधिकारियों की निगरानी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मतगणना के बाद सष्मिता जयप्रकाश साहू को सर्वाधिक 894 मत प्राप्त हुए। सूरज को 131, बिसाहू को 66 तथा भरत को 14 मत मिले। वहीं 17 मत अमान्य घोषित किए गए। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सष्मिता साहू की सास तपस्विनी साहू निर्विरोध सरपंच चुनी गई थीं। कार्यकाल के दौरान उनके आकस्मिक निधन के बाद सरपंच पद रिक्त हो गया था, जिसके चलते उपचुनाव कराया गया।

ग्रामीणों ने एक बार फिर साहू परिवार पर विश्वास जताते हुए सष्मिता साहू को भारी बहुमत से विजयी बनाया। चुनाव में मिली जीत के बाद सष्मिता साहू ने मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने जिस विश्वास और समर्थन के साथ उन्हें सरपंच चुना है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पंचायत क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कराया जाएगा। नवनिर्वाचित सरपंच ने यह भी कहा कि समस्याओं के समाधान और ग्रामीणों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगी। उन्होंने गांव के सर्वांगीण विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया। जोगनीपाली में हुए उपचुनाव के परिणाम को ग्रामीणों ने विश्वास की जीत बताया है।

दारगांव पंचायत सचिव को हटाने की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी

महासमुंद। प्रदेश के मुख्यमंत्री से बागबाहरा विकासखंड अतर्गत ग्राम पचांयत दारगाँव के पंचायत सचिव को स्थानांतरित करने की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में ग्राम पंचायत दारगांव की सरपंच उमा यादव ने कहा है कि दारगांव में पदस्थ सचिव अनिल कुमार साहू पिछले 12 वर्षों से ग्राम पंचायत दारगांव में ही पदस्थ है। पंचायत कार्यालय में अधिकांश समय में अनुपस्थित रहते हैं। पंचायत कार्य में लापरवाही के कारण आम नागरिकों को काम कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। शासन के विकास कार्यों का सही जानकारी के अभाव में लोग इधर-उधर भटकते रहते हैं। सरपंच एवं पंचायत प्रतिनिधियों की अवहेलना भी की जाती है। जिसके कारण आम नागरिकों के बीच आपस में विवाद की स्थिति हो जाती है। सचिव अनिल कुमार साहू को हटाने के लिए मैंने पहले भी जनपद सीईओ, जिला सीइओ और जनपद अध्यक्ष के पास भी आवेदन सौंपा गया था। लेकिन, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पंचायत सचिव अनिल कुमार साहू का तत्काल स्थानांतरण की मांग की है। अन्यथा की स्थिति में आंदोलन करने बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन-प्रशासन की होगी।

13 को होगा एनएचएम कर्मचारियों का प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

- प्रदेशभर से जुटेंगे एनएचएम कर्मचारी और अधिकारी

छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ द्वारा राजधानी के बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में 13 जून को प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस महासम्मेलन के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमनसिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री और जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।

महासम्मेलन में प्रदेश के उप-स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों,

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, मंत्रालय एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत 18 हजार से अधिक कर्मचारी एवं अधिकारी अपने परिवार सहित शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य भेंट कर महासम्मेलन में शामिल होने आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान प्रतिनिधिमंडल में संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी, डॉ. रविशंकर दीक्षित, प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास,डॉ.आलोक शर्मा एवं डॉ. तृप्ति तिवारी उपस्थित रहे।

आयुष विवि का चौथा दीक्षांत कल, बटेंगे 64 स्वर्ण पदक

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

- 49 विद्यार्थियों को वितरित किए जाएंगे 64 स्वर्ण पदक

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विवि का चौथा दीक्षांत समारोह 5 जून को आयोजित किया जाएगा। पं.जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में इसका आयोजन होगा। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तथा विशिष्ट अतिथि लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल होंगे। दीक्षांत भाषण राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नई दिल्ली के राष्ट्रीय विशेषज्ञ पैनल डॉ.वेदप्रकाश मिश्रा देंगे। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024 एवं 2025 में उत्तीर्ण स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। 64 स्वर्ण पदक 49 छात्र-छात्राओं को प्रदाय किया जाएगा। दीक्षांत समारोह का पूर्वाभ्यास 4 जून को सुबह 10:30 बजे पं.जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में होगा।

यू-ट्यूब पर होगा प्रसारण

दीक्षांत समारोह का प्रसारण सुबह 11 बजे से यू-ट्यूब पर होगा। स्वर्ण पदक प्राप्त छात्र-छात्राओं से पूर्व में ही आवेदन प्राप्त कर लिए गए थे। आवेदनकर्ता छात्रों को कल स्वर्ण पदक और उपाधियां वितरित की जाएंगी। दीक्षांत समारोह भारतीय परिधान में होगा। छात्रों को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर आधार पर पृथक-पृथक रंग के उत्तरीय प्रदान किए जाएंगे। कुलपति डॉ. प्रदीप पात्रा स्वागत अकादमिक प्रतिवेदन पेश करेंगे।

खबर संक्षेप

शहर में एक्यूप्रेशर शिविर 7 से

महासमुंद। स्थानीय लायंस क्लब द्वारा 6 दिवसीय एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन 7 जून से 12 जून तक किया गया है। शिविर में एक्यूप्रेशर एवं चुंबकीय पद्धति द्वारा विभिन्न रोगों पुराना सिर दर्द, माइग्रेन, साइटिका, जोड़ों का दर्द, घटनों का दर्द, मोटापा. ब्लडप्रेशर, गैस, कब्ज, एसिडिटी, लकवा, बवासीर, मानसिक तनाव, अवसाद का इलाज किया जाएगा। यह शिविर योग भवन लगेगा। प्रत्येक मरीज का पंजीयन शुल्क 6 दिनों के लिए 200 रुपए निश्चित किया गया है। चिकित्सक डॉ वीआर चौधरी एवं सहयोगी देवाराम जाखड़ जोधपुर अपनी सेवाएं देंगे। शिविर प्रभारी लायन मूलचंद लड्ढा, लायन धर्मेंद्र महोबिया एवं लायन मुकेश चंद्राकर हैं।

सेवा केंद्र उपकार भवन में समर कैंप आज से

महासमुंद। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान 5 से 19 जून प्रातः 7.30 से 9.30 बजे तक कक्षा 8वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए समर कैंप का आयोजन स्थानीय सेवा केंद्र उपकार भवन नयापारा वार्ड में चलाया जाएगा। सेवा केंद्र संचालिका ब्रम्हा कुमारी प्रीति दीदी ने बताया कि इस कैंप में गेम्स वेल्यू, जीवन मूल्य शिक्षण, राजयोग ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विविध प्रतियोगिताएं शामिल रहेंगी। ये आयोजन संस्थान की ओर से निःशुल्क रहेगा।

निधन

भाग्यलक्ष्मी राठौड़

महासमुंद। शहर के स्टेशन रोड निवासी भाग्यलक्ष्मी राठौड़ (71) का निधन हो गया। वे तोषण भाई राठौड़ की धर्मपत्नी, मनीष राठौड़ की माता एवं महेंद्र, भूपेंद्र, खुशाल राठौड़ की भाभी, भरत, राजकुमार राठौड़ की चाची थीं। उनकी अंतिम यात्रा शुक्रवार सुबह 9 बजे निवास स्थान से निकलेगी।

सुविधा: सहकारी समितियों में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक

किसानों के समितियों से खाद लेने के साथ ही खरीफ की तैयारी शुरू

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

- किसानों को सरलता से उपलब्ध हो रहा उर्वरक, जिले में खाद का पर्याप्त भंडारण

खरीफ सीजन को देखते हुए जिले में किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण किया गया है तथा शासन के नियमानुसार किसानों को समय पर खाद का वितरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की सहकारी समितियों में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

उपसंचालक कृषि एफआर कश्यप ने बताया कि जिले की सहकारी समितियों में वर्तमान में 11,310 टन यूरिया, 4,276 टन डीएपी, 1,912 टन पोटाश, 5,888 टन सुपर फास्फेट तथा 3,110 टन एनपीके सहित कुल 26, 496 टन उर्वरकों का भंडारण किया जा चुका है। वहीं किसानों को अब तक 1,365 टन यूरिया, 470 टन डीएपी, 240 टन पोटाश, 466 टन सुपर फास्फेट तथा 264 टन एनपीके का वितरण किया जा चुका है। महासमुंद विकासखंड के ग्राम बम्हनी स्थित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में वर्तमान में 93 टन यूरिया, 57 टन डीएपी, 20 टन सुपर फास्फेट, 7 टन पोटाश तथा 25 टन एनपीके उपलब्ध है। समिति में उर्वरक लेने पहुंचे ग्राम चिंगरौद के किसान गोविंद साहू एवं वेदलाल साहू ने बताया कि उन्हें समिति से बड़ी सरलता और सुगमता के साथ यूरिया एवं डीएपी खाद उपलब्ध हो गया, जिससे खेती-किसानी के कार्यों में सुविधा मिल रही है। इसी तरह ग्राम बरोंडाबाजार स्थित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में उर्वरक लेने पहुंचे ग्राम लाफिनखुर्द के किसान अंजान राम ध्रुव एवं खुमन ध्रुव ने बताया कि उन्हें भी समिति से आसानी से यूरिया एवं डीएपी खाद प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि समय पर उर्वरक उपलब्ध होने से खेती की तैयारियां सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। कृषि विभाग द्वारा लगातार उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की निगरानी की जा रही है, ताकि किसानों को आवश्यकता के अनुरूप समय पर खाद मिल सके।

खरीफ फसल की तैयारी में जुटे किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पूरे प्रदेश में कृषकों को खाद की आपूर्ति कि जा सकें। इसके लिए कृषि भूमि के रकबेवार अलग से व्यवस्था की गई है। जिसमें कृषक (2.5 एकड़ से कम) को एक मुश्त खाद वितरण, सीमांत कृषकों (2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक) को दो किस्तों में (20 दिवस के अंतराल पर) खाद वितरण एवं दीर्घ कृषक (2.5 एकड़ से अधिक) को तीन किस्तो में (20 दिवस के अंतराल पर) उर्वरकों का वितरण निजी एवं सहकारी दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा।

'नीट पेपर लीक पर जवाब देने से भाग रही भाजपा सरकार'

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

- छात्रों की आवाज दबाने के लिए लाठी और दमन का सहारा लेना लोकतंत्र पर हमला का पर्याप्त भंडारण

देश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े नीट पेपर लीक जैसे गंभीर और संवेदनशील मामले में जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में बिलासपुर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के निवास का लोकतांत्रिक घेराव कर रहे एनएसयूआई एवं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, वह न केवल निंदनीय है बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला दमन भी है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस सरकार को छात्रों के सवालों का जवाब देना चाहिए था, वह उनके प्रतिनिधियों पर लाठियां बरसाने में व्यस्त दिखाई दी। आज देश का युवा यह जानना चाहता है कि आखिर नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर कैसे लीक हुआ? लाखों मेहनती विद्यार्थियों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसका संरक्षण प्राप्त था? लेकिन इन सवालों का जवाब देने के बजाय भाजपा सरकार और उसके मंत्री विरोध की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या लोकतंत्र में अब सवाल पूछना भी अपराध हो गया है? क्या छात्रों और युवाओं को अपने भविष्य की चिंता व्यक्त करने का अधिकार नहीं है? जब-जब जनता ने जवाब मांगा है, तब-तब भाजपा ने संवाद की जगह दमन का रास्ता चुना है। यह घटना उसी तानाशाही मानसिकता का एक और उदाहरण है, जिसमें सत्ता में बैठे लोग आलोचना और जनआवाज को सहन नहीं कर पा रहे हैं। नीट पेपर लीक कोई साधारण घटना नहीं थी। यह करोड़ों परिवारों की उम्मीदों पर चोट थी। हजारों विद्यार्थियों ने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, दिन-रात पढ़ाई की, अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगने से उनके विश्वास को गहरा आघात पहुंचा।

ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आज

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

शासन के निर्देशानुसार जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 05 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष ग्राम सभा आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष यह आयोजन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण, विशेषकर स्वच्छ और हरित ग्राम थीम के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आयोजन के लिए समस्त जनपद सीईओ को निर्देश दिए है एवं की गई कार्रवाई से अवगत कराने कहा गया है।

ग्राम सभा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के संबंध में चर्चा कर संकल्प पारित किया जाएगा। जिसमें घरेलू और संस्थागत स्तर पर जैविक कचरे से खाद बनाने को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से कम करने जागरूक किया जाएगा। जल संरक्षण अंतर्गत स्थानीय जल निकायों (तालाब, टैंक आदि) को कचरा डंपिंग से बचाने, इसके साथ ही गांव के स्तर पर जल संसाधन मानचित्रण किया जाएगा।

स्थानीय जागरूकता गतिविधियों में ग्राम सभा के साथ-साथ सार्वजनिक जागरुकता बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर विविध गतिविधियां आयोजित की जाएगी, जिसमें सामूहिक पर्यावरण शपथ ग्रहण समारोह, नुक्कड़ नाटक और रैलियों का आयोजन, सामुदायिक श्रमदान के माध्यम से गाँव के सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों और साझा मैदानों की सफाई एवं पौधरोपण अभियान तथा दीवारों पर कचरा पृथक्कीकरण से संबंधित संदेश व पेंटिंग बनाना आदि शामिल है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत पदाधिकारियों, स्वयं सहायता समूहों, स्वच्छताग्रहियों, स्वच्छता कर्मियों, महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवारों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, स्कूल के बच्चों और शिक्षकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित जाएगी।

राजीव उपाध्यक्ष व स्वप्निल प्रदेश मंत्री नियुक्त

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

सनातन धर्म, सामाजिक जागरुकता एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी, संगठित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से रुद्र सेना का विस्तार किया गया है। संगठन के संरक्षक राजीव लोचन महाराज के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार रुद्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष आलोक पांडे द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई।

घोषित नई कार्यकारिणी में राजीव अवस्थी को प्रदेश उपाध्यक्ष तथा स्वप्निल तिवारी को प्रदेश मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही संगठन को मजबूत एवं सक्रिय बनाने के लिए अन्य पदाधिकारियों को भी विभिन्न दायित्व प्रदान किए गए हैं। नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव अवस्थी एवं प्रदेश मंत्री स्वप्निल तिवारी ने अपनी नियुक्ति पर संगठन के संरक्षक राजीव लोचन महाराज तथा प्रदेश अध्यक्ष आलोक पांडे के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन द्वारा उन पर जो विश्वास व्यक्त किया गया है, उस पर वे पूरी निष्ठा, समर्पण एवं जिम्मेदारी के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि रुद्र सेना केवल एक संगठन नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है।

उन्होंने आगे कहा कि रुद्र सेना द्वारा सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों, सामाजिक जागरुकता अभियानों, पर्यावरण संरक्षण, सेवा कार्यों तथा युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, परंपराओं एवं संस्कारों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। संगठन समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने, युवाओं में राष्ट्रभक्ति एवं सांस्कृतिक चेतना जागृत करने तथा सामाजिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। संगठन के पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में रुद्र सेना प्रदेशभर में अपनी गतिविधियों का विस्तार करते हुए सनातन धर्म, सामाजिक सेवा एवं जनहित के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर राष्ट्र एवं संस्कृति के उत्थान हेतु कार्य करेगी।

नपाध्यक्ष के निर्देश पर बड़ी नालियों की सफाई शुरू

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

- जलभराव की समस्या से निपटने बारिश के पहले बड़ी नालियों की हो रही सफाई

नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू के निर्देशानुसार मानसून पूर्व शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए बड़ी नालियों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है। साहू ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर के सभी मुख्य बड़ी नालियों से सिल्ट, कचरा एवं प्लास्टिक अपशिष्ट को प्राथमिकता से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि बरसात में नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं।

पालिकाध्यक्ष साहू के निर्देश पर सफाई प्रभारी दिलीप चंद्राकर के नेतृत्व में पालिका के सफाई कर्मचारियों ने आज रायपुर रोड के बड़ी नाली की सफाई कर बड़ी मात्रा में कचरा निकाला। जेसीबी के माध्यम से नालियों की गहराई तक साफ कराया गया। साहू ने निर्देशित किया है कि संबंधित विभाग प्रभारी पूरे कार्यों की मानिटरिंग करें, सफाई के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। साहू ने नगरवासियों से भी अपील की है कि वे नालियों में कचरा ना डालें। प्लास्टिक, झिल्लियां डालने से नालियां जाम हो जाती है, जिससे जल निकासी में व्यवधान उत्पन्न होता है। जिससे बाद में काफी परेशानियां होती है। उन्होंने कहा कि घर से निकलने वाले कचरों को पालिका के कचरा एकत्र करने आने वाली स्वच्छता दीदियों को ही दें। साहू ने महासमुंद को स्वच्छ व सुंदर बनाने में समस्त नगरवासियों से सहयोग का आग्रह किया है।

आकाशीय बिजली से बचाव के लिए दामिनी एवं मेघदूत एप उपयोग करने के निर्देश

महासमुंद। वर्षा ऋतु के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से जन एवं पशु हानि की आशंका को देखते हुए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने भारत सरकार द्वारा विकसित दामिनी एप एवं मेघदूत एप का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लोगों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान और सुरक्षा उपायों की जानकारी उपलब्ध कराने सभी जिला, तहसील एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों में पटवारियों, शासकीय शिक्षकों एवं पंचायत सचिवों को इन एप्स के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। दामिनी एप आकाशीय बिजली गिरने की संभावित घटनाओं का पूर्वानुमान लगभग 20 से 31 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से नागरिक समय रहते सतर्क होकर आवश्यक सुरक्षा उपाय अपना सकते हैं तथा जन एवं पशु हानि की घटनाओं को कम किया जा सकता है। एप में आकाशीय बिजली से बचाव के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और सावधानियां भी उपलब्ध हैं। इसी प्रकार मेघदूत एप किसानों के लिए उपयोगी मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करता है। इसमें तापमान, वर्षा की संभावना, हवा की गति एवं दिशा सहित अन्य महत्वपूर्ण मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध रहते हैं, जिससे किसान कृषि कार्यों की बेहतर योजना बना सकते हैं और मौसम जनित जोखिमों को कम कर सकते हैं। दोनों एप गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल में आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों, किसानों एवं पशुपालकों से अपील की है कि वे इन एप्स का उपयोग कर मौसम संबंधी समयपूर्व जानकारी प्राप्त करें तथा आकाशीय बिजली एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहे।

पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ, प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 15 जुलाई

महासमुंद। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस वर्ष 2027 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों (पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री) के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। भारत सरकार की मंशा इन पुरस्कारों के माध्यम से राज्य के सुदूर वनांचलों, ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों से समाज के उन अनसुने और विशेष रूप से गुमनाम नायकों की पहचान करना है, जिन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं कल्याण के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य किया हो। उप संचालक समाज कल्याण संगीता सिंह ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए व्यक्तिगत रूप से भेजे जाने वाले नामांकन ऑनलाइन के माध्यम से भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुरस्कारों के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से अनुशंसा सहित योग्य पात्र व्यक्तियों के स्पष्ट नामांकन प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2026 तक निर्धारित है।

सरस्वती शिविर मथुरा से लौटे बच्चों का हुआ स्वागत

महासमुंद। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा बच्चों को सही दिशा प्रदान करने एवं उनके व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर आधारित सरस्वती शिविर का आयोजन मथुरा में 23 से 29 मई तक किया गया। शिविर में स्वास्थ्य, आदर्श पहनावा, सफलता के सूत्र, एकाग्रता वृद्धि, नारी शिक्षा तथा नशा-मुक्त समाज जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। शिविर में मनोरमा साहू, भारत साहू एवं काजल गुप्ता के मार्गदर्शन में 10 बालिकाओं एवं 4 पालक सदस्यों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में शासकीय हाईस्कूल लाफिनखुर्द की छात्राएं चांदनी साहू, गीतांजलि साहू, जागृति साहू, ईशा साहू, देविका साहू, वर्षा साहू, भावना, धारणी साहू, पुष्पा गुप्ता तथा छात्र उदित, तन्मय और प्रांजल शामिल रहे। इसके अतिरिक्त सरस्वती

शिशु मंदिर महासमुंद की छात्रा वर्षा कन्नौजे ने भी शिविर में सहभागिता की। शिविर से लौटे बच्चों ने इसे विद्यार्थी जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि शिविर में प्राप्त ज्ञान एवं संस्कार उनके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गौरतलब है कि यह शिविर प्रतिवर्ष बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग तिथियों में निःशुल्क आयोजित किया जाता है। शिविरार्थियों के लिए आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था भी की जाती है। विशेष बात यह है कि बच्चों के साथ उनके पालक भी इसमें सहभागिता कर सकते हैं। शिविर से लौटने पर गायत्री शक्तिपीठ महासमुंद द्वारा सभी बच्चों एवं मार्गदर्शकों का स्वागत किया गया तथा शिविर में सहभागिता के लिए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं।

मछली पालन के नाम पर किया गया बड़े तालाब का पानी दूषित, कार्रवाई की मांग

महासमुंद। जिले के बागबाहरा विकासखंड के ग्राम मोहबा, लिटियादादर, टेढ़ीनारा, भिलाईदादर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर ग्राम मोहबा में स्थित बड़े तालाब के पानी को दूषित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि ग्राम मोहबा में एक बड़ा निस्तारित तालाब स्थित है, जिसमें आसपास अनेक गांव की मवेशी एवं ग्रामीण निस्तार करते हैं। गर्मी के दिनों में छोटे-छोटे तालाब सूख जाते हैं, वहीं यह बड़ा तालाब लिटियादादर, टेढ़ीनारा, भिलाईदादर, मोहबा के ग्रामीणों के लिए सहारा बनता है। पिछले वर्ष जनपद पंचायत बागबाहरा ने एक समिति को मछली पालन के लिए यह तालाब लीज में दे दिया है, लीज में देने के बाद समिति ने मछली पालन के नाम पर बड़े तालाब में मुर्गी का वेस्ट मटेरियल और केमिकल युक्त दाना डाल दिया है। जिससे पानी प्रदूषित हो गया है, उसमें नहाने पर ग्रामीणों को खुजली व चर्म की अन्य बीमारियां हो रही है। वहीं मवेशियों के पीने योग्य भी पानी नहीं रहा। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में पानी की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बसुलाडबरी के सरपंच, जनपद सदस्य रेणुका, लक्ष्मी, ओमप्रकाश साहू, दयाराम, राहुल, दिनेश यादव, विपिन, डोमेश यादव, दुलार साहू, मनीराम, ओमन, वेदराम, प्रीतम घनाराम, हेमलाल, लाखन सिन्हा, योगेश दीवान, लालसिंह ठाकुर, राजेंद्र कुमार, बाबूलाल, वेद प्रकाश चंद्राकर, महेश साहू, दयाराम, विवेक आदि के हस्ताक्षर हैं।

पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा त्वरित और कैशलेस उपचार

महासमुंद। सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को समय पर और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पीएम राहत योजना लागू की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क एवं कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव ने बताया कि योजना का लाभ भारत की किसी भी सड़क पर मोटर वाहन से होने वाली दुर्घटना के सभी पीड़ितों को मिलेगा। इसका उद्देश्य दुर्घटना के बाद उपचार में होने वाली देरी को रोकना तथा पीड़ितों की जान बचाना है। योजना को 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे दुर्घटना की सूचना मिलते ही निकटतम अस्पताल की पहचान करने अथवा एंबुलेंस उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इसके माध्यम से पीड़ितों को शीघ्र चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जा सकेगी। योजना के अंतर्गत सामान्य मामलों में दुर्घटना के बाद प्रारंभिक 24 घंटे तथा गंभीर एवं जीवन-रक्षक उपचार की आवश्यकता वाले मामलों में 48 घंटे तक तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे गंभीर रूप से घायल मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा। पीएम राहत योजना का संचालन पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। उपचार से संबंधित क्लेम एवं वित्तीय प्रबंधन मोटर वाहन दुर्घटना कोष के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए ई-डीएआर दुर्घटना रिपोर्टिंग प्रणाली तथा टीएमएस 2.0 अस्पताल क्लेम प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तत्काल सहायता प्रदान करें तथा 112 हेल्पलाइन के माध्यम से आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाकर पीड़ितों को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने में सहयोग करें।

सिंघनपुर में आयोजित समाधान शिविर में कलेक्टर ने आवेदनों के निराकरण की स्थिति का लिया जायजा

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत बसना विकासखंड के ग्राम पंचायत सिंघनपुर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं एवं मांगों के निराकरण के साथ-साथ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान किए गए। समाधान शिविर में जनप्रतिनिधिगण, जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

इस अवसर पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समाधान शिविर का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन, प्राप्त आवेदनों तथा उनके निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर लंगेह ने अधिकारियों को ग्रामीणों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

कलेक्टर ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधे संवाद स्थापित कर आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान करना है। शासन की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे तथा नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े। शिविर में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं एवं मांग संबंधित आवेदनों को अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। कई प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया गया तथा शेष आवेदनों के त्वरित निराकरण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र एवं अन्य सामग्रियों का भी वितरण किया गया।